1	2	3	4	5
17	Rajasthan	710076	140503	23615
18	Sikkim	9961	2182	1442
19	Tamil Nadu	1396016	209696	104647
20	Tripura	52423	14141	3579
21	Uttar Pradesh	3432349	580802	218566
22	West Bengal	717351	287052	51198
23	A & N Islands	863	742	1102
24	Arunachal Pradesh	43978	11358	955
25	Chandigarh	1206	116	63
26	D & N Haveli	1666	677	187
27	Delhi	16845	2146	2328
28	Goa, Daman & Diu	30730	7052	3384
29	Lacshadweep	1510	554	41
30	Mizoram	12493	2623	5637
31	Pondicherry	16845	3142	1478
	ALL INDIA	16562727	3060678	1151586

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सूखे के कारण हुई हानि

1746. **श्री शरद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छतीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस वर्ष सूखे के कारण फसलों को कितनी हानि हुई और क्या छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आदिवासियों के पलायन करने की संभावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना लागू करने की संभावना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने ज्ञापन में दी गई सूचना के अनुसार, राज्य के छत्तीसगढ़ इलाके में सूखे के कारण 10.43 लाख हैक्टार क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। जनजातियों लोगों के पलायन के बारे में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्राकृतिक आपदा के कारण 50 प्रतिशत से अधिक फसल की हानि होने पर, छोटे और सीमान्त किसानों को उनके द्वारा धारित क्षेत्र के लिए 200 रुपये प्रति हैक्टार की दर से कृषि आदान राजसहायता दी जाती है ताकि प्रभावित किसान वैकल्पिक फसल उगा सकें।

(ग) किसी क्षेत्र को सूखे से प्रभावित क्षेत्र घोषित करना राज्य सरकार का काम है।

राजघाट बांध परियोजना के बारे में की गई लेखा-आपत्तियां

1747. **श्री शरद यादव :** क्या जल साधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

बेतवा नदी बोर्ड के अधीन चल रही राजघाट बांध परियोजना की लेखा परीक्षा के दौरान कितनी लेखा-आपत्तियां प्राप्त हुई है ; और

(ख) किन-किन मदों पर आपत्यिां उठाई गई तथा इनमें कितनी-कितनी राशि अर्न्तग्रस्त थी, कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की गई तथा ऐसी चूकों से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्रीबी० शंकरानन्द) (क) महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा राजघाट बांध परियोजना की लेखा-परीक्षा किए जाने के दौरान पिछले तीन वर्षो की लेखा परीक्षी आपत्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	लेखा-परीक्षा निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	आपत्तियों की संख्या
1983–84	14	68
1984–85	15	69
1985–86	16	86

(ख) जिन मदों पर आपत्तियां उठाई गई है उनमें श मिल हैं—ठेकेदारों को भुगतान/सामग्री की लागत की वसूली न करना, निर्माण कार्यो का विभागीय निष्पादन, औजारों एवं संयंत्रों की खरीद, कर्मचारियों को भत्तों का भुगतान आदि संबंधी अनियमितताएं ।

ये लेखा आपत्तियां निपटान के विभिन्न चरणों में हैं । निहित वित्तीय विवक्षा तथा उसके लिए जिनेवर अधिकारियों के बारे में निर्णय इन लेखा आपत्तियों को अन्तिम रूप से निपटाये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है । ऐसी त्रुटियों का भविष्य में न्यूनतम/समाप्त करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बेतवा नदी बोर्ड को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दृष्टि क्षेत्र के अधीन कर दिया गया है ।

(2) इस बोर्ड के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है ।

(3) संविदा दस्तावेजों के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाने वाली अधिकारियों की शक्तियों को कम करने हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

Vehicles for public distribution system

1748. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the number of mobile vans which has been given to different States and Union Territories for Public Distribution System in remote and Tribal areas, statewise;

(b) whether there is any demand for more vehicles; and

(c) if so, what action Government propose to take to cater to the needs of people of these areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) The implementation of Public jDstribution System is the responsibility of the State Government/Union Territory Administration. For streamlining and strengthening the Public Distribution System in Integrated Tirbal Development Project areas, the Central Government provided financial assistance, as a one time measure, during the financial year 1985-86, for the pur-